RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 09 MARCH 2022 TO 15 MARCH 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 27 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

मुंद्रा पोर्ट पर एक साथ आए एपीएसईजेड व आईओसीएल 9 नए कच्चे तेल के टैंकों का निर्माण करेगी Page 2

मप्र में हंगामे के बीच बजट पेश, कोई नया कर नहीं Page 5

रॉयल एनफील्ड के साथ नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीमा भवानी शौर्य एक्सपेडिशन ''एम्पॉवरमेंट राईड - 2022'' Page 7

editoria!

आर्थिक संकट के आसार

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण एक ओर जहां तेल व गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों के दाम में भी तेजी है. इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दोहरी मार का साया मंडराने लगा है. दुनियाभर में महामारी और उससे पैदा हुई मुश्किलों से पहले से ही मुद्रास्फीति का दबाव है. ऐसी स्थिति में विकासशील देशों की मुद्राएं कमजोर हो रही हैं. रूस और यूक्रेन ऊर्जा स्रोतों के महत्वपूर्ण उत्पादक व वितरक होने के साथ खाद्य वस्तुओं के भी बड़े आपूर्तिकर्ता हैं. यूरोप समेत कई देशों को वे खनिज पदार्थों के अलावा कृषि में इस्तेमाल होनेवाले फर्टिलाइजर और रसायन भी मुहैया कराते हैं. यदि रूस और यूक्रेन का मसला युद्ध के स्तर तक नहीं पहुंचता, तो अगले तीन से नौ महीने की अवधि में वैश्विक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी आने की उम्मीद की जा सकती थी. पर अब स्थिति बदल चुकी है और ऊर्जा मूल्यों में कमी होने की गुंजाइश नहीं है. जानकारों की मानें, तो यह भी कह पाना मुश्किल है कि तेल के दामों की मौजूदा बढ़ोतरी किस हद तक जा सकती है. अधिकतर विकासशील देशों को न केवल ईंधन का आयात करना पड़ता है, बल्कि इनमें से कई भोजन सामग्री के लिए भी दूसरे देशों पर आश्रित हैं. कीमतों के कारण उनका आयात खर्च तो बढ़ेगा ही और घरेलू व बाहरी मुद्रास्फीति के चलते उन्हें वस्तुओं के अधिक दाम देने पड़ेंगे क्योंकि उनकी मुद्रा के मूल्य में भी कमी आ रही है. जल्दी स्थिति में सुधार न हुआ, तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक भंवर में फंस सकती हैं. भारत सहित अनेक विकासशील देशों के घरेलू बाजार में मांग को लेकर पहले से ही स्थिति संतोषजनक नहीं है. मुद्रास्फीति की वजह से इसमें और कमी आ सकती है. बीते कुछ समय से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध से काला सागर से ढुलाई तो ठप है ही, हवाई मार्ग भी बंद है. इसके साथ ही कई देशों ने रूस पर कठोर पाबंदियों की घोषणा की है. रूस की ओर से भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है. इस प्रकार यूरोप में हो रहे युद्ध की चपेट में अन्य महादेशों की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी आ चुकी हैं. अन्य क्षेत्रों में झटकों को बर्दाश्त कर पाना एक हद तक संभव भी है, पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित होता है. भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की भागीदारी लगभग आधी है. फिलीपींस, चीन और रूस में यह आंकड़ा 30 फीसदी से ज्यादा है, जबकि यूरोपीय देशों में इसका अनुपात 10 से 15 प्रतिशत और अमेरिका में लगभग आठ फीसदी है. इससे साफ इंगित होता है कि मुद्रास्फीति उभरते बाजारों पर सबसे अधिक असर डालेगी और उन देशों की मुद्रा को कमजोर करेगी. इससे कोरोना काल के बाद की उपलब्धियां भी हाथ से निकल सकती हैं.

अमेरिका का रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध का फैसला

पुतिन के खिलाफ बाइडेन का बड़ा एक्शन

वाशिंगटन। एजेंसी

यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले रूस को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसना है। ऐसे इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की अपील को दरकिनार कर चुका है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर अटैक के प्रतिशोध में रूस की अर्थव्यवस्था पर टोल को सख्त करते हुए, रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से कई देशों ने रूस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि, रूस पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है और युद्ध जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुए हालात में ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी शेल ने रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद बंद करने की मंगलवार को घोषणा की। शेल ने एक बयान में कहा कि वह चरणबद्ध तरीके से रूस से सभी हाइड्रोकार्बन- कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की खरीद बंद करेगी। इसके साथ ही शेल ने रूस में अपने सर्विस स्टेशनों और अन्य परिचालन को भी बंद करने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस से तेल की खरीद जारी रखने के लिए शेल की आलोचना की थी।

अब फिर से ईरान और वेनेजुएला के साथ संभव है क्रूड का व्यापार

दुनिया पर होगा असर

वाशिंगटन। एजेंसी

यूक्रेन-रूस युद्ध के 13 दिन बीत चुके हैं। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर होने लगा है। तमाम देशों के लगाए ढेरों प्रतिबंध झेलने के बाद भी रूस यूक्रेन पर अपनी कार्रवाई को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर अब नए समीकरण बनने लगे हैं। रूस पर वैश्विक प्रतिबंधों के चलते महंगे क्रूड की धार में फंसे भारत-अमेरिका सहित कई देशों के सामने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालना बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि रूसी कंपनियों ने भारत सहित कई देशों को डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने की पेशकश की है। लेकिन इसमें कई पेंच हैं। यह भी आशंका है कि अमेरिका और पश्चिमी देश खफा हो जाएंगे। रूस से तेल और गैस एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के दायरे में नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक खरीदारों के रूसी तेल की खरीद से परहेज से क्रूड 140 डॉलर के 13 साल के हायर स्टेज पर है। इस बीच, अमेरिका ने रूस से तेल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस संबंध में घोषणा कर दी। वहीं ब्रिटेन ने 2022 के आखिर तक रूसी तेल-गैस के इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस मामले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो वैकल्पिक सप्लायर खोजेगी। यही नहीं, अब सऊदी अरब के साथ पुराने दुश्मन वेनेजुएला और ईरान से ऑयल डील की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने अफसरों को वेनेजुएला भेजा है। अब तक अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध खराब रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से क्रूड लिया जा सकता है। परमाणु डील पर बातचीत में ऑयल भी शामिल है।

ऐसा हुआ तो टूट जाएगी रूसी अर्थव्यवस्था

तेल ऐसी पूंजी है, जो संकट में फंसे रूस के लिए संजीवनी बन सकती है। रूस रोज 80 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है और दुनिया के 80 देशों में सप्लाई करता है। उसके तेल की 25 फीसदी खपत यूरोप और 15 परसेंट चीन में है। भारत में 2% ही रूसी खपत है। रूसी उपप्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने कहा, रूसी तेल पर बंदिश से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा हो जाएगा। यूरोपीय बाजारों में इतनी जल्दी इसकी आपूर्ति की भरपाई संभव नहीं होगी। वहीं रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने चेतावनी दी है कि युद्ध के चलते क्रूड की कीमतें 300 डॉलर बैरल तक पहुंच सकती हैं। पहले ही 40 साल की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 14 साल में सबसे ज्यादा हैं।

भारत को सस्ते तेल का ऑफर क्यों दे रहा रूस

मुश्किल में घिरी रूसी कंपनियां भारत सहित कई देशों को 25-27ङ्क छूट देकर क्रूड बेचने का ऑफर दे रही हैं। हालांकि भारत के लिए इसे लाने में कई समस्याएं हैं। लॉजिस्टिक समेत खर्च के बाद लागत उतनी ही पड़ेगी, जितनी अभी है।

टैंकर-बीमा-भुगतान

फ्री ऑन बोर्ड मॉडल में तेल देने की बात कही जा रही है। यानी खुद ले जाइए। भारत 80% तेल पश्चिमी देशों के टैंकर से लाता है। ये देश रूस से क्रूड के लिए टैंकर देंगे? भारतीय कंपनियां खुद बीमा करती हैं। इसके बाद विदेशी कंपनियों से समर्थन दिया जाता है। प्रतिबंधों के बाद पश्चिमी देशों की कंपनियां रूसी तेल पर बीमा देने को तैयार नहीं। तेल का कारोबार डॉलर में होता है। अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट तक रूस की पहुंच रोक दी गई है। भारतीय कंपनियां इसके लिए राह तलाशने की कोशिश कर रही हैं। पहले रुपए और रुबल में कारोबारी संभावना पर काम हुआ है।

कैसे आ सकता है रूसी क्रूड

नरेंद्र तनेजा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञ और आरएस शर्मा, पूर्व अध्यक्ष ओएनजीसी के अनुसार युद्ध के बावजूद रूस का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है। दो सरकारों के बीच समझौते और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट बिक्री से इंपोर्ट किया जा सकता है। एक बार तेल स्पॉट बाजार में आ जाए तो राष्ट्रीयता नहीं रह जाती। यह मंडी में आए फल-सब्जी जैसा हो जाता है। ऐसे में नफा-नुकसान और आयात की सुगमता व भुगतान की शर्तें मायने रखती हैं। सभी पैमानों पर सुविधाजनक हो तो रूस की पेशकश का लाभ उठाया जा सकता है।

अब रूस का गोल्ड रिजर्व बैन करने की मांग

अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने मंगलवार को रूस के गोल्ड रिजर्व पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की मांग की है। रूस के पास 130 अरब डॉलर का सोने का भंडार है। सीनेटरों के मुताबिक वह अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सोने का इस्तेमाल कर सकता है।

मुंद्रा पोर्ट पर एक साथ आए एपीएसईजेड व आईओसीएल आईओसीएल 9 नए कच्चे तेल के टैंकों का निर्माण करेगी

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने मुंद्रा में आईओसी के कच्चे तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं। आईओसीएल, एपीएसईजेड के मुंद्रा पोर्ट पर अपने मौजूदा क्रूड ऑयल टैंक फार्म का विस्तार करेगा, जिसके बाद यह मुंद्रा में अतिरिक्त 10 एमएमटीपीए कच्चे तेल को संभालने और मिश्रण करने में सक्षम होगा। साथ ही यह अपनी आईओसीएल के पानीपत रिफाइनरी (हरियाणा) के विस्तार को भी सहयोग प्रदान करेगा। आईओसीएल भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पानीपत रिफाइनरी की क्षमता को 66ऱ बढ़ाकर 25 एमएमपीटीए कर रहा है।

एपीएसईजेड के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री करण अदाणी ने कहा कि, 'मुंद्रापोर्ट एक प्रमुख इकोनॉमिक गेटवे है, जो मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए, भारत के उत्तरी भीतरी इलाकों की सेवा करता है। हम अपनी

साझेदारी को और मजबूत करने तथा आईओसीएल का सहयोग करने के लिए गर्व महसूस करते हैं, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईओसीएल के भरोसेमंद लॉन्ग टर्म पार्टनर 'एपीएसईजेड' मुद्रा में हमारे मौजूदा सिंगल बॉय मूरिंग (एसबीएम) को अतिरिक्त 10 एमएमटीपीए कच्चे तेल को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया है। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट का लगभग आधा हिस्सा अपने पास रखने वाले आईओसीएल की रिफाइनिंग क्षमता 80.55 एमएमटीपीए और 15 हजार किलोमीटर से अधिक का पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी के लिए मौजूदा 15 एमएमटीपीए कच्चे तेल की आवश्यकता का एक हिस्सा मुंद्रा पोर्ट के एसबीएम में संभाला जाता है। मुंद्रा एसबीएम, तट से 3-4 किमी दूर स्थित है जहां बेहद विशाल क्रूड कैरियर्स (वीएलसीसी) कच्चे तेल को उतारते हैं। यहां समुन्द्र के नीचे एक पाइपलाइन, इस कच्चे तेल को एसबीएम से कच्चे तेल के टैंक फार्म तक और उसके बाद मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन (एमपीपीएल) के द्वारा पानीपत रिफाइनरी तक पहुंचाती है।

आईओसीएल वर्तमान में अदाणी के मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक कच्चे तेल के टैंक फार्म का संचालन कर रहा है, जिसमें कुल 720,000 केएल की क्षमता वाले 12 टैंक मौजूद हैं। जबकि 9 नए टैंकों के जुड़ने से भंडारण क्षमता बढ़कर 1,260,000 केएल हो जाएगी, जिससे मुंद्रा पोर्ट आईओसीएल के लिए अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट आधारित, कच्चे तेल का भंडारण केंद्र बन जाएगा। इसके साथ ही आईओसीएल द्वारा एमपीपीएल पाइपलाइन क्षमता को 17.5 एमएमटीपीए तक बढ़ाया जाएगा। आईओसीएल बोर्ड ने दिसंबर 2021 में कच्चे तेल के टैंकों और एमपीपीएल वृद्धि के लिए 9000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी थी। मुंद्रा पोर्ट पर यह विस्तार परियोजना, एपीएसईजेड में राज्य द्वारा संचालित आईओसीएल के भरोसे को दर्शाती है, जिसे इसके बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, टर्नअराउंड समय में सुधार और इस प्रकार अपने ग्राहकों के लिए मूल्यवान बनने के अपने रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

बड़े दिनों बाद आई शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 650 अंक से अधिक उछला रिलायंस के शेयरों में तेजी

मुंबई। एजेंसी

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के लाभ में रहने से बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में 650 अंक से अधिक तेजी आई जबकि एनएसई निफ्टी भी 175 अंक उछल गया। दोपहर 12 बजे 636.45 अंक यानी 1.19ऱ की बढ़त के साथ 54,060.54 अंक पर और निफ्टी 164.55 यानी 1.03ऱ बढ़त के साथ 16,178 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

सेंसेक्स में टेक महिंद्रा , रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड , सन फार्मा , इन्फोसिस और डॉ. रेड्डीज के शेयर लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर पावर ग्रिड, टाटा स्टील , एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर नुकसान में रहे। पिछले सत्र में तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के अंत में 581.34 अंक यानी 1.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 53,424.26 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मंगलवार को 150.30 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,013.45 अंक पर बंद हुआ था। इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.16 प्रतिशत बढ़कर 131.3 डॉलर प्रति बैरल हो गया। शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को सकल आधार पर 8,142.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

सीएनजी के दाम बढ़े, पेट्रोल-डीजल पर अभी 'फैसला' नहीं

नयी दिल्ली। एजेंसी

राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में सीएनजी के दाम मंगलवार को 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ा दिए गए। वहीं पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में अधिक स्पष्टता आने के इंतजार में अभी रुकी हुई है। दिल्ली में सीएनजी की खुदरा बिक्री करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की वेबसाइट पर नई दरों की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 57.51 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आईजीएल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर समय-समय पर सीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ाती रही है। इस साल यानी 2022 में ही सीएनजी के दाम में अबतक करीब चार रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुके हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी अब एक रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। मंगलवार से इन शहरों में सीएनजी का दाम 59.58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। दरअसल सीएनजी की कीमतें राज्यों में अलग-अलग होती हैं। स्थानीय कर लगने के बाद इनकी कीमतों में फर्क आ जाता है। अगर मुंबई की बात करें, तो वहां सीएनजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहां पर सीएनजी के दाम 66 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। आईजीएल ने पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर का मतदान सोमवार को खत्म हो जाने के बाद पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में फौरन बढ़ोतरी की संभावना पहले से जताई जा रही थी। लेकिन अभी तक पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कीमतों में तत्काल वृद्धि करने के बजाय अभी दो दिनों तक बदलते अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर रखने का फैसला किया है। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर जबकि मुंबई में 109.98 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। वहीं डीजल दिल्ली में 86.67 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 94.14 रुपये प्रति लीटर के भाव पर है।

गवर्नर दास ने 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई सेवा का शुभारंभ किया

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एक नई सेवा का शुभारंभ किया, जिसके जरिये 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपयोगकर्ता सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। गौरतलब है कि यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत के लगभग छह साल बाद इस सेवा की पेशकश की जा रही है। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वे यूपीआई '123पे' नाम से शुरू की गई इस सेवा के जरिये डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और यह सेवा साधारण फोन पर काम करेगी। दास ने कहा कि अब तक यूपीआई की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध हैं, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक यूपीआई लेनदेन 76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 41 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है, जब कुल लेनदेन का आंकड़ा 100 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

एक अनुमान के मुताबिक देश में 40 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के पास सामान्य फीचर फोन हैं। डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि इस समय यूपीआई सेवाएं यूएसएसडी-आधारित सेवाओं के जरिये ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यह काफी बोझिल है और सभी मोबाइल परिचालक ऐसी सेवाओं की अनुमति नहीं देते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फीचर फोन उपयोगकर्ता अब चार तकनीकी विकल्पों के आधार पर कई तरह के लेनदेन कर सकते हैं। इनमें आईवीआर (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स) नंबर पर कॉल करना, फीचर फोन में ऐप की कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल आधारित विधि और ध्वनि आधारित भुगतान शामिल हैं। इस सेवा के जरिये उपयोगकर्ता दोस्तों और परिवार को धन भेज सकते हैं, विभिन्न बिलों का भुगतान कर सकते हैं। वाहनों के फास्टैग को रिचार्ज करने तथा मोबाइल बिलों का भुगतान करने की सुविधा भी इसमें मिलेगी। दास ने डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी के साथ साइबर सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि हमारी प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने एनपीसीआई से यूपीआई को अन्य देशों में ले जाने के प्रयास जारी रखने के लिए कहा, ताकि वैश्विक समुदाय को उनके नवाचारों से लाभ मिल सके। दास ने मंगलवार को डिजिटल भुगतान के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तैयार किया है। 'डिजिसाथी' नाम की इस हेल्पलाइन की मदद वेबसाइट - 'डिजिसाथी डॉट कॉम' और फोन नंबर - '14431' और '1800 891 3333' के जरिये ली जा सकती है।

कैबिनेट ने लैंड मोनेटाइजेशन के लिए NLMC के गठन को मंजूरी दी

सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनएलएमसी (NLMC) को 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भवनों, अधिशेष भूमि और सरकारी एजेंसियों के मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनएलएमसी को 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरकारी कंपनियों के लैंड मोनेटाइजेशन में एडवाइजरी की भूमिका निभाएगी। यह उस जमीन की पहचान करेगी, जिनको मोनेटाइज किया जाना है। इसकी रूपरेखा तय करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों की बेची जा रही या बंद होने के कगार पर चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों की अधिशेष भूमि और इमारतों का मुद्रीकरण करने के लिए एक एनएलएमसी की स्थापना को मंजूरी दी। एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एइर्ऐं) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा।

इस समय सीपीएसई के पास जमीन और भवनों की प्रकृति में काफी अधिशेष, अप्रयुक्त और कम उपयोग की गई नॉन-कोर संपत्तियां हैं। रणनीतिक विनिवेश या बंद होने वाले सीपीएसई के लिए इन सरप्लस लैंड और नॉन-कोर एसेट्स का मोनेटाइजेशन उनके मूल्य को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। एनएलएमसी इन एसेट्स के मोनेटाइजेशन का समर्थन और काम करेगा। यह निजी क्षेत्र के निवेश, नई आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने के लिए इन कम उपयोग की गई संपत्तियों के उत्पादक उपयोग को भी सक्षम करेगा।

3,500 एकड़ जमीन का मोनेटाइजेशन

अभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मोनेटाइजेशन के लिए करीब 3500 एकड़ जमीन और दूसरे नॉन-कोर एसेट्स को आगे रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे एसेट्स को कॉरपोरेशन के पास ट्रांसफर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, एसेट्स को लीज या किराये पर देने या उन्हें किसी दूसरे तरीके से मोनेटाइज करने का हक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के पास होगा। ऱ्श्ण इसके साथ निवेश और कमर्शियल या रेजिडेंशियल उद्देश्यों के लिए एसेट्स को विकसित भी कर सकता है। ऱ्श्ण किराये या लीज के जरिए इनकम भी जुटा सकता है।

ज़ेडएफ ने भारत में किया अपने ग्लोबल आईटी सेंटर का विस्तार

पुणे, हैदराबाद, चेन्नई में विस्तार की योजना

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अपनी 4-सूत्रीय रिफ्रेश इंडिया रणनीति के तहत, ज़ेडएफ भारत क्षेत्र के व्यापक आइटी टैलेंट प्रतिभा का भविष्य में और लाभ उठाएगा। कंपनी का उद्देश्य? पुणे, हैदराबाद और चेन्नाई में अपने वैश्विक आईटी सेंटर का विस्त्रा करना है। यह सेंटर्स वैश्विक स्तर पर ग्रुप में डिजिटलीकरण को सहयोग करने के लिए आईटी उत्पाद, सेवाओं एवं डिजिटल नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारतीय आईटी टीम ग्रुप की डिजिटल पहलों को तेजी देने में मदद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। इसके लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मशीन लर्निंग, एनालिटिक्सक, इंडस्ट्री 4.0, ब्लॉकचेन के साथ क्लाउड तकनीकों का सहारा लिया जाएगा।

ज़ेडएफ सीवीएस अनेक वर्षों से अपने आईटी उत्पाद, सेवाओं और डिजिटल नवाचार क्षमता के लिए भारत में आईटी टैलेंट का सफलता के साथ लाभ उठाता रहा है। ग्राहकों की ओर से बढ़ती माँग और व्यवसाय के विस्तार की ज़रुरत पूरा करने के लिए, ज़ेडएफ अब अपने तीन आईटी केन्द्रों में अपना कार्यबल बढ़ाने की योजना बना रहा है। इन आईटी केन्द्रों से प्राप्त कुशलताओं और क्षमताओं पर भारी फोकस का प्रयोग सम्पूर्ण इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा मोबाइल ऐप्लिकेशंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा आदि में वैश्विक उपक्रम रूपांतरणों के लिए किया जाएगा।

ज़ेडएफ ग्रुप के सीआइओ, डॉ. जोर्गेन स्टर्म ने कहा, 'हम भारत क्षेत्र और ज़ेडएफ ग्रुप के लिए कुशलताओं और क्षमताओं को बढ़ाते हुए एक छलांग लगाना चाहते हैं। डिजिटलीकरण में हमारे ग्रुप की पहलों को तेज करने में आगे विस्तार और ग्लोबल आईटी सेंटरों का लाभ उठाने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।' आईटी रीजन इंडिया के लिए सीआइओ, डॉ. मिलन कुमार ने कहा, 'तकनीक हमारे व्यवसाय की रीढ़ है और ज़ेडएफ हमेशा से तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहा है, जिससे गतिशीलता पारितंत्र को फ़ायदा हुआ है। भारत में प्रमाणित नवाचार-शक्ति के साथ विशाल आईटी टैलेंट पूल को देखते हुए ज़ेडएफ के ग्लोबल आईटी सेंटर के विस्तार, उत्पाद, सेवाएँ और डिजिटल नवाचार टीम यहाँ भविष्य में ज़ेडएफ को एक डिजिटल उपक्रम में बदलने के लिए निर्माण के एक महत्वपूर्ण साधन बनेंगे।'

यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी छात्रा को भारत ने सुरक्षित निकाला

बांग्लादेश और नेपाल के छात्रों को भी दी मदद

नई दिल्ली। एजेंसी

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सहित पड़ोसी देशों के छात्रों को निकाल रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान सहित कई और देशों की मदद की है और उन्हें युद्धक्षेत्र से सुरक्षित निकाला है। इसी दौरान एक पाकिस्तानी छात्रा आसमा शफीक ने भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। एक वीडियो में आसमा ने कहा है कि मैं यूक्रेन स्थित भारतीय एंबेसी की बहुत शुक्रगुजार हूं। हम बहुत मुश्किल हालात में थे लेकिन उन्होंने हमें सुरक्षित बाहर निकाला है। मैं इसके साथ ही भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को भी मदद के लिए धन्यवाद देती हूं। भारतीय एंबेसी की वजह से हम सुरक्षित वापस घर वापस जा रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 'ऑपरेशन गंगा' के तहत यूक्रेन से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत नेपाल और ट्यूनेशिया के छात्रों को भी बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के महोत्तरी जिल के रोशन झा को भी भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षित निकाला था। रोशन ने इसके लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया था। बाद में काठमांडू स्थित भारतीय एंबेसी ने सूचित किया था कि भारत सरकार पोलैंड के रास्ते सात और नेपाली नागरिकों को निकाल रही है।

उद्योगों में नेतृत्व वाली भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम : सर्वे

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

कंपनियों के लैंगिक समानता पर जोर देने के बावजूद उद्योगों में नेतृत्व वाली भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। सोमवार को जारी एक सर्वेक्षण में यह कहा गया। मर्सर के 'भारत कुल पारिश्रमिक सर्वेक्षण (टीआरएस)-2021' सर्वेक्षण के अनुसार, प्रवेश स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की दिया जाने वाला वेतन आदि भुगतान 95-99 प्रतिशत था। वहीं यह अनुपात मध्यम से वरिष्ठ स्तर की श्रेणी पर आते काफी कम हो जाता है। सर्वेक्षण के अनुसार, मध्यम से वरिष्ठ श्रेणी में महिलाओं का पारिश्रामिक पुरुष सहयोगियों के मुकाबले घटकर 87 से 95 प्रतिशत रह जाता है। सर्वेक्षण में कहा गया कि वेतन में कमी, पदोन्नति की धीमी गति, वृद्धि के अवसरों और प्रतिनिधित्व वाली भूमिकाओं जैसे मुख्य कारणों से महिलाओं का वेतन अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में कम रहता है। यह सर्वेक्षण 900 से अधिक कंपनियों, नौकरी से जुड़े 5,700 से अधिक कार्यों और 14 लाख से अधिक कर्मचारियों के आंकड़ों पर आधारित है।

रूस-यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से कच्चे तेल की बढ़ती कीमत बिगाड़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाल

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस-यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को देखें तो लगता है कि यह जंग आने वाले वक्त में तमाम समस्याएं पैदा करेगी। कुछ मामलों में तो यह नजर भी आने लगी है। जैसे कि कच्चे तेल की कीमत। फिलहाल हालत यह है कि तेल की कीमत जून, 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। कच्चे तेल (क्रूड आयल) की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 130 डालर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। हमारे देश के लिए यह चिंताजनक है। भारत में हर दिन 55.50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है।

तथ्य यह है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। हम अपनी इस जरूरत की पूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारा देश अपनी आवश्यकताओं का 85 प्रतिशत कच्चा तेल दुनिया के 40 देशों से आयात से पूरा करता है। इसमें सबसे ज्यादा आपूर्ति मध्य-पूर्व देशों (विशेषतः ईरान) और अमेरिका से होती है, जबकि युद्ध में उलझे रूस से भी दो प्रतिशत कच्चा तेल मंगाया जाता है। इस कच्चे तेल को भारत की रिफाइनरी कंपनियां शोधन करने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोलडीजल) में बदलती हैं। यहां से इन उत्पादों को 100 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जो देश के कुल निर्यात का 13 प्रतिशत है। वाहनों को सड़कों पर दौड़ाने से लेकर उद्योगों में लगने वाले पेट्रोलियम पदार्थों की हमारी मांग सालाना तीन-चार प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। अनुमान है कि अगले एक दशक में भारत में प्रतिदिन कच्चे तेल की खपत 70 लाख बैरल की मात्रा को पार कर लेगी। बढ़ती कीमत क्यों है एक बुरी खबर : कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का कितना गहरा असर होता है इसका अंदाजा वर्ष 2014 की स्थितियों से हो जाता है। तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डालर प्रति बैरल को पार कर गई थी। उस दौरान हमारा देश अत्यधिक मुद्रास्फीति (महंगाई) से जूझ रहा था। चालू खाते का घाटा सिर के पार चला गया था। इन सबके असर से देश

के विकास की दर मंद पड़ गई थी। आज रूस-यूक्रेन से पैदा हालात पर नजर डालें तो कह सकते हैं कि यह जंग हमारी ऊर्जा सुरक्षा की मुहिम को खतरे में डालने जा रही है। किसी को मालूम नहीं है कि यह युद्ध कब तक जारी रहेगा। ऐसे में तेल की कीमत की उछाल का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत कच्चे तेल की कीमत से सीधे जुड़ी हुई है। ऐसे में विकास दर का टिकाऊ होना इसकी कीमत पर निर्भर करता है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि अगर कच्चे तेल की कीमत 70 से 75 डालर प्रति बैरल के बीच स्थिर रहती है तो देश की विकास दर 8 से 8.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह एक अच्छे भविष्य का अनुमान था, पर रूस-यूक्रेन के युद्ध ने इस समीकरण को बिगाड़ दिया है। 130 डालर प्रति बैरल को पार कर गए कच्चे तेल का सीधा अर्थ यह है कि इससे देश के चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। यही नहीं, तेल की यह महंगाई अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गति को धीमा करते हुए विकास को भी प्रभावित करेगी। पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा खर्च होने के कारण जनता दूसरी चीजों पर अपना खर्च घटा देगी। सरकार को तेल पर सब्सिडी बढ़ानी होगी जिससे बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के लिए उसके पास खजाने में ज्यादा रकम नहीं बचेगी। तेल की महंगाई सरकार के

कीमतें बढ़ने की वजह

यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कुछ ही समय पहले कच्चे तेल को कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा था। वर्ष 2020 में एक अवसर ऐसा आया था, जब कच्चे तेल की कीमत शून्य डालर से नीचे गिर गई थी। इसे बेचने वाले को प्रतीकात्मक रूप से अपनी जेब से पैसा भरना पड़ा था, क्योंकि इसकी कीमत माइनस 40 डालर हो गई थी। कोरोना के चलते दुनियाभर में लगे लाकडाउन के कारण चौपट होते कारोबार के कारण कच्चा तेल निकालने की योजनाएं ठप पड़ गई थीं, तेल कंपनियोंमें निवेश रुक गया था और नए ढांचों का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। महामारी के पहले हर दिन शेल तकनीक से 40 लाख बैरल तेल का उत्पादन करने वाली अमेरिकी कंपनियों ने नया निवेश रोककर तेल कुएं ढक दिए थे और कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी थी, लेकिन दो साल के अंदर ऐसा करिश्मा हुआ कि जीरो डालर प्रति बैरल की कीमत वाला तेल 130 डालर से ऊपर फर्राटा भर रहा है। असल में कोरोना का असर कम होने के साथसाथ जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाओं ने गति पकड़ी तो तेल की कीमतों में भी उछाल आने लगा। इस बीच रूस-यूक्रेन के युद्ध के कारण बिगड़ी आपूर्ति श्रृंखला के चलते तेल बाजार का पारा इतना गर्म हो चला है कि इसे छूते ही डर लग रहा है। हाहाकार मचने की अहम वजह यह है कि बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन गिने-चुने देश ही करते हैं। मध्य-पूर्व यानी खाड़ी देशों के बाहर अमेरिका, रूस और वेनेजुएला ही बड़े उत्पादक हैं। नौबत यह आ गई है कि निर्यातक देश अमेरिका तक को आज अपनी जरूरतों के लिए तेल आयात करना पड़ रहा है।

रणनीतिक तेल भंडारों का सहारा

कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से पैदा तनाव को सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका- यूरोप समेत तमाम देशों में महसूस किया जा रहा है। मौजूदा संकट के समाधान के लिए अमेरिका सहित कुछ देशों ने अपने रिजर्व में रखे छह करोड़ बैरल कच्चे तेल को जारी करने का फैसला किया है। इसमें से आधी मात्रा यानी तीन करोड़ बैरल अकेले अमेरिका ने लुसियाना और टेक्सास में स्थित अपने रणनीतिक तेल भंडारों से निकालकर जारी करने का फैसला किया है। इन दो अमेरिकी राज्यों में स्थित 60 सुरंगों में करीब 70 करोड़ बैरल कच्चा तेल भंडारित करके रखा जाता रहा है। हाल में अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने जो बाइडेन प्रशासन को सूचित किया था कि इनमें फिलहाल 58 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इन रणनीतिक तेल भंडारों का निर्माण वर्ष 1973 में अरब देशों द्वारा तेल की सप्लाई रोके जाने की स्थितियों में किया था। तब योम किपुर युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा इजरायल को समर्थन देने के फैसले के चलते अरब देश नाराज हो गए थे। इसके चलते वर्ष 1974 तक आते-आते कच्चे तेल की कीमत में चार गुना बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में तेल पर निर्भर अपने औद्योगिक ढांचे को ढहने से बचाने के लिए अमेरिका ने इन तेल भंडारों का निर्माण किया था। हालांकि इनके रखरखाव पर सालाना 20 करोड़ डालर खर्च हो जाते हैं, लेकिन इन रणनीतिक तेल भंडारों की बदौलत अमेरिका कई महीने तक बाहर से तेल खरीदे बिना अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वर्ष 1991 में खाड़ी युद्ध और वर्ष 2005 में कटरीना चक्रवाती तूफान से हुए विनाश के दौरान पैदा हुए ऊर्जा संकट को अमेरिका ने इन्हीं रणनीतिक तेल भंडारों की बदौलत हल कर किया था। भारत ने भी रणनीतिक तेल भंडार बना रखे हैं। भारत के पास तीन रणनीतिक तेल भंडार हैं-विशाखापत्तनम (13.3 लाख मीट्रिक टन), मंगलुरु (15 लाख मीट्रिक टन) और पादुर (25 लाख मीट्रिक टन)। इन तेल भंडारों का संचालन भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व द्वारा किया जाता है। खबर है कि भारत ने भी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के मद्देनजर अपने रणनीतिक तेल भंडारों से कच्चा तेल जारी करने की तैयारी कर ली है। हाल में सरकार ने बयान दिया है कि तेल बाजार की अस्थिरता एवं कच्चे तेल की कीमत पर अंकुश लगाने के उपायों के तौर पर देश रणनीतिक तेल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि भारत के पास अमेरिका जितना विशाल रणनीतिक तेल भंडार नहीं है। वर्ष 2019-20 की खपत पैटर्न के अनुसार हमारे देश के रणनीतिक तेल भंडारों में मौजूद कुल 53.3 लाख मीट्रिक टन की मदद से करीब 9.5 दिनों के कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

कीमत पर कैसे लगे लगाम

हालांकि कच्चे तेल की कीमत पर अंकुश रखने के प्रयास भी इधर शुरू किए गए हैं। विश्लेषक बता रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (633 अरब डालर) कीमत पर लगाम लगाने के मामले में एक अच्छा विकल्प है। इसकी मदद से तेल उत्पादक देशों को कीमत नीचे लाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसी तरह यदि तेल उत्पादक देश उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें तो भी समस्या से फौरन राहत मिल सकती है। भारत के बारे में सुझाव यह है कि देश अपनी ऊर्जा नीति को विकेंद्रीकृत करे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों को समुद्री तटों पर चलने वाली तेज हवाओं की मदद से पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में अभी भी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत दुनिया में सबसे कम है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन की ठोस योजनाएं बनाकर संकट के समाधान की उम्दा राहें खोली जा सकती हैं। ध्यान रखना होगा कि तेल की कीमत अर्थशास्त्र के मांग-आपूर्ति के साधारण नियम के मुताबिक घटती-बढ़ती है। इस समय मांग में अचानक हुई वृद्धि से इसकी कीमत में आग लगी है। ऐसे में यदि वे उपाय अपनाएं जाएं, जिनसे तेल की मांग में कमी आ जाए तो इसकी कीमत घटती चली जाएगी। इस बारे में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया और कार) को दिए जा रहे प्रोत्साहन को एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। अगर आने वाले वक्त में ज्यादातर वाहन बिजली से चलने लगेंगे तो देश कच्चे तेल की कीमत की क्रूरता से बच जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ाकर और लोगों को उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करके भी यह तस्वीर बदली जा सकती है और तेल आयात के खर्च से बचते हुए इसके विपरीत प्रभावों को खत्म किया जा सकता है।

दो साल बाद 27 मार्च से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करेगा भारत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं 27 मार्च से फिर शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें करीब दो साल से बंद हैं। नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं 23 मार्च, 2020 से स्थगित थीं। हालांकि, जुलाई 2020 से करीब 35 देशों के साथ 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है।

नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज्य सिंधिया ने कहा, "उद्योग से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श और कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी को देखते हुए हमने 27 मार्च, 2022 से

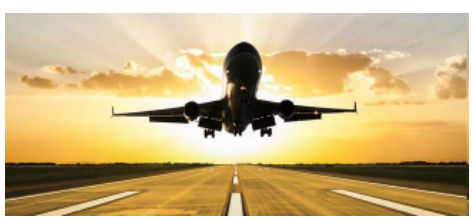

अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है।" उन्होंने कहा कि इस निर्णय के साथ एयर बबल व्यवस्था को हटा दिया गया है। सिंधिया ने कहा, "इस निर्णय के साथ मैं आश्वस्त हूं कि विमानन उद्योग नयी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।" मंत्रालय ने बयान में कहा कि 27 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 10 फरवरी को जारी दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन के साथ किया जाएगा।

बयान में कहा गया है, "विश्वभर में कोरोना रोकथाम टीकाकरण अभियान को मान्यता देने और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ परामर्श के बाद सरकार ने 27 मार्च से भारत से आने-जाने वाली अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है।" मंत्रालय ने कहा कि भारत के लिए और भारत से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं का निलंबन 26 मार्च, 2022 तक जारी रहेगा और एयर बबल व्यवस्था भी तब तक ही रहेगी।

गौरतलब है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 26 नवंबर, 2021 को 15 दिसंबर, 2021 से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के नए संस्करण ओमीक्रोन को देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद मंत्रालय ने अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को शुरू करने का फैसला टाल दिया था।

मप्र में हंगामे के बीच बजट पेश, कोई नया कर नहीं

पहली बार चाइल्ड बजट

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच राज्य का बजट पेश किया। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं, पहली बार राज्य में चाइल्ड बजट पेश किया गया है।

बजट घोषणाएं...

•लगभग 3 हजार किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव।

•प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।

•मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2022-23 में 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

•वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 48 हजार 800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

•कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान गत वर्ष से लगभग 8 हजार 829 करोड़ रुपये अधिक होकर 40 हजार 415 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो एक कीर्तिमान है।

•एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटों को बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 217 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

•उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

•प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 50 करोड़ का प्रावधान किया है।

•नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के संबंध में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे गति देने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी भी बनाई है।

हंगामे के बीच बजट पेश

कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम का स्मरण, नमन करते हुए रामराज्य स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करें। कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। इस बीच, देवड़ा ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा। देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश लक्ष्य हासिल कर रहा है। राज्य ने महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं। यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्प है। वित्त मंत्री ने कोरोना के प्रबंधन, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किए गए प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने भी हरसंभव कोशिश की है और सफलता हासिल की है।

बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं

■लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई हैं। बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी।

■सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश कर रही है। 18 साल से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं को अलग से दिखाया जाएगा। इससे उनके लिए चल रही योजनाएं एक नजर में सामने आएंगी।

■ग्राम एवं नगर दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों में यह भावना विकसित होगी कि मेरे गांव या शहर के विकास में क्या मदद कर सकते हैं?

■फसलों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जाएगी।

■पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

■भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़, छतरपुर का राजगढ़ पैलेस निजी निवेशकों को दिया जाएगा।

■360 नए सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य। इसके लिए 7 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया है।

■उच्च शिक्षा के लिए 12 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान। स्वास्थ्य के लिए 13642 करोड़ रुपये।

■बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 52 हजार 511 करोड़ रुपये। कुल प्राप्ति 2 लाख 49 हजार 152 करोड़ रुपये और व्यय 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपये।

■पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया। कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी अधिक राजस्व वसूली का अनुमान बजट में।

■स्वरोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।

■जनवरी-2022 तक 3,048 किमी सड़कें बनाई गई। इस बार 4 हजार किमी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें बनाने के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

■स्वसहायता समूहों के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है।

■आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। बजट में मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना प्रस्तावित है।

■किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए घर-घर पशु चिकित्सा सुविधा देने की कल्पना की गई है।

■एटीएफ पर वैट को घटाकर 4ड किया है। इससे प्रदेश में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

■वंचित तबकों के लिए यह बजट समर्पित है। अजजा रोजगारमूलक योजना प्रस्तावित है।

■तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है।

■15 जनजाति कन्या विद्यालयों को नए भवनों में संचालित करने का लक्ष्य है।

■आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

■15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है।

■मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा था। इसमें हमने सफलता हासिल की है।

■स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। जिला चिकित्सालयों में कोविड-19 सेंटर बनाया गया था। सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

■बुरहानपुर जिले के हर घर में नल योजना का 100ड कार्यान्वयन हुआ है। अब जिले के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है।

■13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। अन्य विभागों में भी रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी।

■निजी संस्थाओं में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके जरिए प्रदेश के युवाओ को रोजगार के साधन दे रहे हैं।

■उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन दे रहे हैं। प्रक्रियाओं को सहज बनाया गया है। 3 दिन में उद्योग शुरू किया जा सकता है।

■21 हजार 865 करोड़ रुपये की 381 परियोजनाओं के निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

■भारत सरकार की ओर से उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। रतलाम, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। 41 हजार से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे।

■इथेनॉल और जैव ईंधन के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है।

■इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क बनाए गए हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें, इसके लिए कोशिश हो रही है।

■स्वरोजगार के लिए ढाई लाख लोगों को हर माह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है।

IL&FS डिफॉल्ट के बाद EPFO ने पहली बार प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के बॉन्ड में किया निवेश

नई दिल्ली। एजेंसी

कॉरपोरेट बॉन्ड में सबसे बड़े निवेशकों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईइध) ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (प्ऊइण) द्वारा जारी किए गए 10,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड में से 65 फीसदी से अधिक सब्सक्रिप्शन लिया। इसके बाद एसबीआई पेंशन (एँध झहेग्दह) और प्रोविडेंट फंड (ईदन्हू इल्ह) का स्थान है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। यह पहली बार है जब ईपीएफओ ने 2018 के अंत में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (र्घ्ईए) के डिफॉल्ट के बाद से किसी भी निजी संस्था द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश किया है। एचडीएफसी ने 7।18 फीसदी वार्षिक कूपन दर पर 10 वर्षों में मैच्योर होने वाले नॉन-कंवर्टिवल डिबेंचर जारी करके 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉन्ड पर निर्धारित कूपन नए 10-वर्षीय बेंचमार्क बांड वार्षिक यील्ड से केवल 17 बेसिस प्वाइंट अधिक है और समान परिपक्वता वाले स्टेट लोन की तुलना में 6 बेसिस प्वाइंट कम है। ब्रोकरेज फर्म के एक डीलर ने कहा कि ईपीएफओ की मांग को ध्यान में रखते हुए AAऔर उससे ऊपर की रेटिंग वाले अन्य जारीकर्ता बेहतर दरों और निवेशकों के बड़े वर्ग से मजबूत मांग का लाभ उठाने के लिए बाजार का दोहन कर सकते हैं।

डिफॉल्ट के बाद प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड में रोक दिया था निवेश

ईपीएफओ ने निजी कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड में अपना निवेश रोक दिया है। लेकिन सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में सक्रिय निवेशक बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि र्घ्ईए और समूह की कंपनियों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और रिलायंस कैपिटल द्वारा अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर चूक के बाद उन्हें बहुत दबाव का सामना करना पड़ा था।लेकिन, हाल ही में एचडीएफसी में निवेश के बाद रुझान उलट होता दिख रहा है क्योंकि वे सरकारी प्रतिभूतियों में आपूर्ति के अभाव में और कॉरपोरेट बॉन्ड में राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा कम जारी करने में अधिक निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। दिसंबर के बाद से भारी धन उगाहने के बाद साल के अंत तक होम फाइनेंस कंपनी के बाजार में उतरने की संभावना नहीं है। बाजार के सूत्रों से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, एचडीएफसी ने पिछले तीन महीनों में 14,500 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा दिसंबर के पहले हफ्ते में था।

क्या होता है एनसीडी?

नॉन-कंवर्टिवल डिबेंचर्स सरकार या कंपनी जारी करती है। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस सीधे लोगों से लोन लेते हैं। इसके बदले कंपनी आपको एक टोकन देती है जिसमें आपके पैसे पर मिलने वाली ब्याज दर लिखी रहती है। जब आप एनसीडी में पैसा लगाते हैं तो आप किसी कंपनी या बड़े ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली पैसा उधार देते हैं। इसमें कंपनियां अक्सर एफडी में मिलने वाली ब्याज दर से ज्यादा ब्याज देती हैं।

होलाष्टक कब से कब तक, जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं

10 मार्च, गुरुवार से होलष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। होली से पहले 8 दिनों तक होलाष्टक रहता है। होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस साल होलाष्टक 10-17 मार्च 2022 तक रहेंगे। इसके बाद होलिका दहन और इसके अगले दिन होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, होलाष्टक के दौरान भगवान कृष्ण की उपासना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य व नया काम शुरू करना वर्जित माना जाता है।

होलाष्टक के दौरान क्या करें

होलाष्टक के दौरान भगवान की पूजा व अराधना करने का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान के भक्त को कष्ट सहना पड़ता है। इस दौरान मंत्रों का जाप, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान करना लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है।

होलाष्टक के दौरान क्या न करें

शास्त्रों के अनुसार, होलाष्टक के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। क्योंकि इस अवधि में भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद को तरह-तरह के कष्ट मिले थे। ऐसे में होलाष्टक के दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। इसके अलावा गोद भराई, सगाई आदि भी होलाष्टक के दौरान नहीं करनी चाहिए।

होलाष्टक को लेकर प्रचलित कथाएं-

1. भक्त प्रहलाद- पौराणिक कथा के अनुसार, राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्रीहरि की भक्ति से दूर करने के लिए आठ दिनों तक कठिन यातनाएं दी थीं। आठवें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जिसे वरदान प्राप्त था, वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और जल गई थी लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे।

2. रति पति कामदेव- कहते हैं कि देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए कई दिनों में कई तरह के प्रयास किए थे। तब भगवान शिव ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उनके अपराध के लिए शिवजी से क्षमा मांगी, तब भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया।

ज्योतिषीय कारण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के होते हैं। ग्रह-नक्षत्र के कमजोर होने के कारण इस दौरान जातक की निर्णय क्षमता कम हो जाती है। जिससे गलत फैसले से हानि की संभावना रहती है।

होलिका दहन का शुभ मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर 18 मार्च 2022 को दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च को रात 09 बजकर 20 मिनट से देर रात 10 बजकर 31 मिनट तक है। यानी होलिका दहन की कुल अवधि 01 घंटा 10 मिनट की है।

करियर में सफलता पाने अपनाएं इनमें से कोई एक उपाय

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

हर व्यक्ति चाहता है कि उसे काम में सफलता हासिल हो। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। अगर आपको भी मेहनत का उचित फल नहीं नहीं मिल पा रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वास्तु टिप्स जिससे आपको लाभ मिलेगा। वास्तु शास्त्र में घर, ऑफिस और करियर आदि के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जानें करियर में सफलता पाने के वास्तु टिप्स-

सफाई का रखें ध्यान- ऑफिस या घर पर जिस जगह आप बैठते हैं, वहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने डेस्क पर बेवजह का सामान फैला कर न रखें। वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि डेस्क पर सामान फैला कर रखने से तरक्की में बाधा आती है।

रोशनी वाली जगह- अगर आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ऑफिस का काम जिस जगह भी बैठकर करते हैं वहां भरपूर रोशनी आए। सूर्य की किरणों को वास्तु में बेहद शुभ माना जाता है।

सीट पर रखें ये चीजें- करियर में सफलता पाने के लिए सीट पर क्रिस्टल रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। डेस्क पर बांस का पौधा रखना भी लाभकारी माना जाता है।

इस दिशा में रखें मुख- वास्तु शास्त्र के अनुसार, आपकी सीट उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुंह उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होने से आपको लाभ मिलता है।

इस रंग के न पहनें कपड़े- वास्तु शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना गया है। काला रंग नकारात्मकता को दर्शाता है। ऐसे में करियर में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए काले रंग के कपड़े ना पहनें।

एस-400 मिसाइल पर गरमाई राजनीति

भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंध लगाना बड़ी मूर्खता होगी- रिपब्लिकन सीनेटर

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता व प्रभावशाली सीनेटर टेड क्रूज ने राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से कहा कि रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर काटसा के तहत कोई भी प्रतिबंध लगाना 'बड़ी मूर्खता' होगी। काटसा एक अमेरिकी कानून है, जो प्रशासन को रूस से हथियारों की खरीद करने वाले देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

सीनेट की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान क्रूज ने कहा, 'ऐसी रिपोर्ट हैं कि बाइडन प्रशासन धरती के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवरसरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (काटसा) के तहत प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह फैसला असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण होगा।'क्रूज ने कहा, 'भारत कई क्षेत्रों में अहम साझेदार है। हाल के कुछ वर्षों में भारत व अमेरिका का गठबंधन और गहरा तथा मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडन प्रशासन में यह आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहा है।' यूक्रेन में रूसी हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव पर मतदान के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए क्रूज ने कहा कि ऐसा करने वाला वह एकमात्र देश नहीं है। उन्होंने समिति के समक्ष एक अन्य सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले एक साल में बाइडन प्रशासन के अंतर्गत भारत के साथ संबंध काफी खराब हुए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव के दौरान भारत के उपस्थित नहीं रहने से जाहिर है। 'रूस को लेकर भारत की हैं कुछ मजबूरियां' यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआइबीसी) के अध्यक्ष अतुल केशप ने सांसदों से कहा, 'भारत की रूस के साथ मजबूरियां हैं और पड़ोसी चीन के साथ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर संबंध तनावपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकी के रूप में हमारी भारतीयों के प्रति, उनके लोकतंत्र व उनकी व्यवस्था के बहुलवाद को लेकर आत्मीयता है।'

विदेश मंत्रालय में कई पदों पर काम कर चुके केशप ने सदन की विदेश मामलों की समिति द्वारा हिंद-प्रशांत पर आयोजित संसद की सुनवाई के दौरान अपनी राय साझा की। संसद सदस्य अबिगैल स्पैनबर्जर ने पूछा, 'भारत, रूस व रूसी हितों पर दुनियाभर में कई देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों को लागू करने का कैसा प्रयास करेगा?' केशप ने कहा, 'मेरी राय है कि सभी देश अपने फैसले खुद लेते हैं। वे सभी जानकारियां लेते हैं और निर्णय लेते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा होगा।' उन्होंने कहा कि भारत हाल में विशेष रूप से व्यापार व्यवस्था पर बहुत अधिक महत्वाकांक्षा और उद्यमशीलता की भावना दिखा रहा है। केशप ने कहा, 'अगर आप ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया व इजराइल के साथ उनकी बातचीत को देखें, तो पाएंगे कि वे उन देशों के साथ अपने रिश्ते को कैसे प्राथमिकता दे रहे हैं।'

यूक्रेन संकट लंबा खिंचने पर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर विचार कर सकता है भारत

नयी दिल्ली। एजेंसी

रूस-यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख व्यापार क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय नकद अंतरण की समस्या पैदा होने की स्थिति में भारत निर्यातकों के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली मुहैया कराने पर विचार कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद प्रमुख पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के चलते सरकार इस संभावना पर विचार कर सकती है। पश्चिमी देशों ने रूस को अंतर-बैंकिंग प्रणाली 'स्विफ्ट' से भी बाहर कर दिया है। इस कदम से रूस को वैश्विक व्यापार से अलग-थलग करने का इरादा है। एक सूत्र ने कहा, ''भारत यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में अपने विदेश व्यापार के समक्ष मौजूद परिस्थितियों पर करीबी निगाह रखे हुए है। अगर प्रतिकूल हालात लंबे समय तक बने रहते हैं और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख व्यापार क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय नकदी अंतरण में समस्या पेश आती है तो फिर भारत उन्हें वैकल्पिक भुगतान प्रणाली देने पर भी विचार कर सकता है।'' रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों को रूस के अलरोसा से समर्थन के आश्वासन मिले हैं। वैश्विक हीरा उत्पादन में करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली अलरोसा अपने 10 प्रतिशत हीरे भारत को बेचती है। भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात में करीब 50 प्रतिशत हिस्सा हीरे का ही है। हालांकि, अभी तक रूस से अपरिष्कृत हीरे की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है लेकिन रत्न एवं आभूषण उद्योग रूस को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर किए जाने को लेकर फिक्रमंद है। इस संबंध में सरकार भी निर्यातकों एवं हीरा आयातकों के संपर्क में बनी हुई है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत और रूस के बीच रुपये एवं रूबल में कारोबार की वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था लागू की जाए। फियो के महासचिव अजय सहाय ने कहा कि संगठन ने सरकार को इस वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने ग्लांजा के नए संस्करण की बुकिंग शुरू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी प्रीमियम हैचबैक गाड़ी ग्लांजा के नए संस्करण के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने एक बयान में कहा कि ग्राहक इस मॉडल को ऑनलाइन या डीलर के जरिए 11,000 रुपये का भुगतान करके बुक कर सकते हैं। टीकेएम में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट (बिक्री और रणनीतिक विपणन) अतुल सूद ने कहा, ''नई ग्लांजा उन लोगों के लिए है जो आधुनिक और किफायती विकल्प चाहते हैं।'' टोयोटा ग्लांजा 2019 में बाजार में आई थी। अब तक कंपनी ने घरेलू बाजार में 66,000 से अधिक ग्लांजा कारें बेची हैं।

रॉयल एनफील्ड के साथ नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक सीमा भवानी शौर्य एक्सपेडिशन ''एम्पॉवरमेंट राईड - 2022''

इन्दौर। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए संगठनात्मक मिशन, बीएसएफ सीमा भवानी शौर्य एक्सपेडिशन ''एम्पॉवरमेंट राईड - 2022'' का उद्घाटन 8 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से 10 बजे श्रीमती नूपुर सिंह, प्रेसिडेंट, बीएसएफ वाईव्स वैलफेयर एसोसिएशन (बीडब्लूडब्लूए) द्वारा किया गया। बीएसएफ सीमा भवानी शौर्य एक्सपेडिशन ''एम्पॉवरमेंट राईड- 2022'' महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करती है और इसका उद्देश्य महिलाओं की सकारात्मक विज़िबिलिटी बनाना है, ताकि देश में युवा लड़कियों और महिलाओं को देश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और बीएसएफ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। रॉयल एनफील्ड के साथ गठबंधन में आयोजित इस राईड में बीएसएफ सीमा भवानी ऑल-वूमैन डेयरडेविल मोटरसाईकल टीम के 36 सदस्य इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही के नेतृत्व में 5280 किलोमीटर लंबी कठिन राईड पर जाएंगे और कन्याकुमारी के रास्ते में पड़ने वाले सभी बड़े शहरों से गुजरते हुए चेन्नई की ओर बढ़ेंगे तथा पूरे देश में महिला सशक्तीकरण के संदेश का प्रसार करेंगे। इस अवसर पर, मुख्य अतिथि ने देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर रोशनी डाली और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में फोर्स के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर मोहित धर जयाल, चीफ ब्रांड ऑफिसर, रॉयल एनफील्ड ने सीमा भवानी शौर्य एक्सपेडिशन ''एम्पॉवरमेंट राईड- 2022'' को देश के सुरक्षा बल की सेवा करने के रॉयल एनफील्ड के अप्रतिम रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव बताया। उन्होंने इस बात में असीम गर्व महसूस किया कि इस एक्सपेडिशन का नेतृत्व ऑल वूमैन सीमा भवानी टीम कर रही है, जिसने निकट इतिहास में अपने कौशल और साहस के अतुल्य प्रदर्शन से लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। अब

वो इस अद्भुत यात्रा के दौरान अनेक महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी। उन्होंने अगले 20 दिनों के इस एडवेंचर के लिए टीम को शुभकामनाएं दीं।

उद्घाटन के अवसर पर मौजूद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रतिष्ठित महिला ओलिंपियन, महिला खिलाड़ी, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि, श्रीमती नूपुर सिंह, प्रेसिडेंट, बीडब्लूडब्लूए द्वारा सम्मानित किया गया। उनमें शामिल हैं:

1.प्रीतम रानी सीवच, पूर्व कप्तान, भारतीय महिला हॉकी टीम, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता

2.रोज़ालिड एल रल्टे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी

3.येंडाला सौंदर्या, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी

4.प्रणति नायक, ओलिंपिक जिमनास्ट

5.सीमा पुनिया अंतिल, ओलिंपिक डिस्कस थ्रोअर

6.सुचिका तरियाल हूडा, अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी एवं मेडलिस्ट, सैफ गेम्स

बीएसएफ सीमा भवानी शौर्य एक्सपेडिशन ''एम्पॉवरमेंट राईड- 2022'' देश के कोने-कोने में जाएगी और दिल्ली में इंडिया गेट से शुरू होकर पंजाब में वागाह अट्टारी बॉर्डर और गुजरात में स्टेचू ऑफ लिबर्टी से होते हुए अंत में चेन्नई, तमिलनाडु में रॉयल एनफील्ड इंडिया के

टेक्निकल सेंटर में संपन्न होगी। इस सफर में साहसी सीमा भवानी राईडर्स रॉयल एनफील्ड की ऑल न्यू क्लासिक 350 पर सवार होकर पूरे देश से गुजरेंगी। यह मोटरसाईकल अधुनिक अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की टाईमलेस क्लासिक मोटरसाईकल बनाने की समृद्ध विरासत से प्रेरित है, तथा लंबे समय से सशस्त्र बलों की भरोसेमंद साथी है। यह एक्सपेडिशन चंडीगढ़, अमृतसर, अट्टारी, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, गांधीनगर, केवड़िया, नासिक, सोलापुर, हैदराबाद, अनंतपुर, बैंगलोर, और कन्याकुमारी से गुजरेगी और 28 मार्च, 2022 को चेन्नई में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। यह टीम स्कूली बच्चों, एनसीसी कार्यकर्ताओं और युवाओं, विभिन्न राईडिंग समुदायों एवं अन्य लोगों से मिलकर महिलाओं की क्षमताओं के बारे में जागरुकता बढ़ाएगी और पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों एवं भेदभाव से स्वतंत्रता पर बल देगी।

18 महीने में पहली बार सोने का भाव 55,000 रुपये के पार

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से सोने की कीमतें 18 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार को सोने की कीमत 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई। जबकि चांदी की कीमतों में भी उछाल आया। एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा सोने के भाव में 1।4 फीसदी तेजी दर्ज की गई। वहीं, मई वायदा चांदी की कीमत में 1।8 फीसदी की बढ़त आई है। पिछले सत्र में 19 महीने के शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक बाजारों में आज सोने के भाव स्थिर रहे। हाजिर सोना 2,053।99 डॉलर प्रति औंस पर सपाट था। मंगलवार को करीब नौ महीने के उच्च स्तर को छूने के बाद हाजिर चांदी 1 फीसदी बढ़कर 26।66 डॉलर प्रति औंस हो गई। वैश्विक बाजारों में अगस्त 2020 में सोना 2,072 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जबकि भारत में यह बढ़कर 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। अमेरिका द्वारा रूसी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद सोने और चांदी में तेजी आई। वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी रही और उच्च स्तर से दोनों कीमती धातुओं में मुनाफावसूली देखी गई।

सोने-चांदी की नई कीमतें

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार को अप्रैल वायदा सोने का भाव 1।4 फीसदी बढ़कर 55,190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जबकि मई वायदा चांदी की कीमत 1।8 फीसदी चढ़कर 72,698 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन संकट सोने की सुरक्षित पनाह मांग को समर्थन दे रहा है, जबकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और मजबूत अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लाभ को सीमित कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने इस महीने दरों में बढ़ोतरी का समर्थन किया, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी हुई, जबकि डॉलर डेढ़ साल से अधिक वर्षों में सोमवार के उच्च स्तर के पास रहा। सोना अमेरिका की बढ़ती ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील है, जो नॉन-यील्डिंग बुलियन को धारण करने की अवसर लागत को बढ़ाता है। उच्च दरें भी डॉलर को बढ़ावा देती हैं, जिससे ग्रीनबैक-कीमत वाली धातु पर दबाव पड़ता है। लाइव मिंट की रिपोर्ट में मेहता इक्विटीज के वीपी कमोडिटीज राहुल कलंत्री ने कहा, सोने में 2024-1995 डॉलर का सपोर्ट है, जबकि 2064-2082 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस का रेसिस्टेंस है। रुपये के संदर्भ में सोने में 53,154-52,450 रुपये का सपोर्ट है जबकि प्रतिरोध 55,440-56,240 रुपये का रेसिस्टेंस है। चांदी में 69650-68,420 रुपये का सपोर्ट जबकि 73,000-74,180 रुपये का रेसिस्टेंस है। घरेलू ब्रोकरेज जियोजित ने कहा कि सोने में तेजी जारी रह सकती है, जबकि कीमतें 2000 डॉलर से ऊपर रह सकती हैं।

गुजरात में डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र को स्थापित करने को मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र (ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रैडिशनल मेडिसिन) की स्थापना को बुधवार को मंजूरी दे दी । इसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में की जायेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।

इसके तहत भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना की जायेगी। सरकारी बयान के अनुसार, इस केंद्र की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत की जायेगी।

इस केंद्र की स्थापना के लिए गतिविधियों के समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) का गठन किया गया है। जेटीएफ में भारत सरकार, भारत के स्थायी मिशन, जिनेवा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य आयुष प्रणालियों को दुनिया भर में स्थापित करना, पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना तथा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना है।

बयान के अनुसार, इसका मकसद शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से डब्ल्यूएचओ पारंपरिक औषधि सूचना विज्ञान केंद्र की अवधारणा को सुनिश्चित करना एवं प्रासंगिकता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ए गेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 13 नवंबर, 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत में डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम की स्थापना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक कल्याण, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता के केंद्र के रूप में उभरेगा।

चीनी मिलों ने इस साल 62 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे किए: मिल संघ

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय चीनी मिलों ने मौजूदा चीनी सत्र में अब तक 62 लाख टन चीनी की आपूर्ति करने के निर्यात सौदे किए हैं। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एक अक्टूबर 2021 से शुरू चीनी विपणन सत्र 2021-22 में अब तक चीनी मिलों ने 62 लाख टन चीनी निर्यात करने के सौदे किए हैं। इनमें से 47.84 लाख टन चीनी विदेशों को भेजी भी जा चुकी है। बयान के मुताबिक चीनी मिलों की तरफ से निर्यात की जाने वाली यह चीनी सरकारी सब्सिडी से मुक्त है। इस साल चीनी का निर्यात सरकारी सब्सिडी के बगैर किया जा रहा है।

News यू केन USE

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे चढ़ा

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और घरेलू शेयर बाजार के मजबूत होने के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 76.78 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के गहराने के कारण रुपये में तेजी सीमित रहेगी, यह अधिक अस्थिरता का भी सामना कर सकता है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76.90 पर खुला। फिर यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 22 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 76.78 के स्तर पर आ गया। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत गिरकर 99.01 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 2.59 प्रतिशत बढ़कर 131.29 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

यूक्रेन संकट भारत की आयात क्षमता पर डाल सकता है असर: रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकते है। एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया है कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में भी पड़ सकता है। क्रिसिल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में रूस को भारत से किया जाने वाला निर्यात 2.55 अरब डॉलर पर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.87 अरब डॉलर के निर्यात से 36.1 प्रतिशत अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के शुरूआती नौ महीनों में भारत से यूक्रेन को 37.2 करोड़ डॉलर (0.2 प्रतिशत) का निर्यात किया गया। हालांकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्पात और एल्युमीनियम जैसे कुछ क्षेत्रों को बढ़ती कीमतों से फायदा भी हो सकता है।

निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना मार्च, 2024 तक बढ़ी

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले और बाद में रुपये में लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना की अवधि मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है। पिछले साल अप्रैल में इस योजना को जून तक और फिर सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष श्रेणी के एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों के लिए योजना के तहत ब्याज समानीकरण दरों को संशोधित कर दो प्रतिशत और तीन प्रतिशत कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक, ''सरकार ने रुपया मूल्य में निर्यात से पहले और बाद के कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना को 31 मार्च, 2024 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार एक अक्टूबर, 2021 से शुरू होकर 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा।

जमनाबाई नरसी स्कूल ने जीता #ican स्कूल चैलेंज का पहला संस्करण

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

1971 में स्थापित हुए, मुंबई के सबसे पुराने स्कूलों में से एक जमनाबाई नरसी स्कूल ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने वाले विचारों को खोजने के लिए अदाणी समूह द्वारा आयोजित एक स्कूल स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता क्ष्र्म्ह स्कूल चैलेंज अपने नाम किया है। 'क्लीनर फ्यूचर' की थीम पर आयोजित हुई इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पहले एडिशन को जीतने के लिए देशभर के लगभग 240 स्कूलों द्वारा 50 बीट 748 आइडिया पेश किए गए।

पवार पब्लिक स्कूल, भांडुप, और अंजुमन-ए-इस्लाम के मुस्तफा फकीह उर्दू हाई स्कूल, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे, जिसे संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्डी, एडवोकेट अफरोज शाह, मिशन ग्रीन मुंबई के संस्थापक और वाटर हीरो 2019 अवार्डी श्री सुभाजीत मुखर्जी, और अदाणी ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज प्रो अरुण शर्मा के एक प्रतिष्ठित पैनल ने जज किया। अदाणी ग्रुप के हेड सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रो. अरुण शर्मा ने कहा, 'भविष्य में ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी।' 'आज के बच्चे वह पीढ़ी होंगे जो उन लड़ाइयों का नेतृत्व करेंगे और लड़ेंगे। हमें क्ष्र्म्ह स्कूल चैलेंज जैसी राष्ट्रीय पहलों का नेतृत्व करने के लिए खुश हैं। मेरा मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं हमारे यंग चेंज एजेंट्स को इस बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, कि वे अपना और देश का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं।' जूरी के सदस्य एडवोकेट अफरोज शाह ने कहा कि 'हमने आज भी बहुत से यंग लीडर्स को देखा है। हर छोटा बच्चा कुछ न कुछ अलग लाता है जो राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकता है।'

जूरी सदस्य श्री सुभाजीत मुखर्जी ने कहा, 'इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक बच्चा विजेता है।' उन्होंने यहां जो शानदार नवाचार प्रस्तुत किए, वे इस बात का प्रमाण हैं कि भारत में युवा इको-चैंपियनों की कोई समस्या नहीं है। क्ष्र्म्ह स्कूल चैलेंज जैसी पहल देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है कि हमारी अगली पीढ़ी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर केंद्रित रहे।

जमनाबाई नरसी स्कूल को 1.5 लाख रुपये का शीर्ष पुरस्कार जिताने वाला यह आईडिया एमआईटी ऐप इन्वेंटर प्लेटफार्म पर बनाया गया एक बेहतरीन 'हाउस-होल्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम' था, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था। पवार पब्लिक स्कूल, भांडुप, और अंजुमन-ए-इस्लाम के मुस्तफा फकीह उर्दू हाई स्कूल, जिन्होंने अपने दूसरे और तीसरे स्थान के लिए 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये जीते, उन्होंने क्रमशः अपशिष्ट हीट का दोहन करने और इसे उद्देश्यपूर्ण व भविष्य के उपयोग के लिए एलईडी टीईजी बनाने के लिए समाधान के रूप में प्रस्तावित किया। जबकि फ्यूचर फॉरवर्ड 'जीरो वेस्ट स्कूल' को प्लास्टिक और ई-कचरे की मात्रा को व्यवस्थित रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

'डिजिटल रुपया' लाने का फैसला रिजर्व बैंक की सलाह से सोच-समझकर लिया गया : सीतारमण

बेंगलुरु। एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और 'डिजिटल रुपया' लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह से सोच-समझकर लिया गया है। सीतारमण ने मंगलवार को यहां इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिजिटल रुपये पर एक सवाल के जवाब में कहा, ''यह केंद्रीय बैंक- भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सोच-समझकर किया गया फैसला है... हम चाहते हैं कि वे इसे जिस तरह से लाना चाहें, उस तरह डिजाइन करें, लेकिन हम केंद्रीय बैंक से इस साल मुद्रा लाने की उम्मीद करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं, क्योंकि आज के दौर में देशों के बीच होने वाले थोक भुगतान, संस्थानों के बीच बड़े लेनदेन और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंकों के बीच बड़े लेनदेन, ये सभी डिजिटल मुद्रा के जरिये बेहतर ढंग से हो सकते हैं।'' क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि हितधारकों से परामर्श के बाद सरकार इस बारे में फैसला करेगी। उन्होंने कहा, ''परामर्श जारी है .... इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति का सुझाव देने के लिए स्वागत है। परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रालय इसपर विचार करेगा। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम किसी कानूनी अनिवार्यता से परे नहीं जा रहे हैं, उसके बाद हम इसपर अपना रुख सामने लाएंगे।'' यह पूछने पर कि क्या वह भारत में क्रिप्टो के लिए भविष्य देखती हैं, उन्होंने कहा, ''कई भारतीयों ने इसमें अत्यधिक संभावनाएं देखी हैं और इसलिए मुझे इसमें राजस्व की गुंजाइश दिखाई देती है।'' हाल में पेश किए गए आम बजट के बारे में सीतारमण ने कहा कि बजट में 'अमृत काल' का उल्लेख अधिक से अधिक डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के संबंध में है। उन्होंने कहा कि इस बजट में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की घोषणा की गई है। सीतारमण ने कहा कि भारत को इनकी जरूरत है, क्योंकि आजादी के 75 वर्षों में एक राष्ट्रीयकृत बैंकिंग नेटवर्क के बावजूद बैंकिंग और वित्तीय समावेशन पूरा नहीं हो सका।

एलआईसी के आईपीओ का रास्ता साफ, दस्तावेजों के मसौदे को सेबी की मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए 63,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि सेबी ने एलआईसी द्वारा 13 फरवरी, 2022 को दाखिल दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी एक महीने से भी कम समय में मिल गई है।

डीआरएचपी के अनुसार, आईपीओ के तहत सरकार एलआईसी के 31.6 करोड़ इक्विटी शेयर या कंपनी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी के पॉलिसीधारकों और कर्मचारियों को आईपीओ में न्यूनतम शेयर मूल्य पर छूट मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकक कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स द्वारा एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य निकाला गया है। 30 सितंबर, 2021 तक कंपनी का अंतर्निहित मूल्य 5.4 लाख करोड़ रुपये था। अंतर्निहित मूल्य बीमा कंपनी में शेयरधारकों के एकीकृत मूल्य के आधार पर निकाला गया है। हालांकि, डीआरएचपी में एलआईसी के बाजार मूल्यांकन का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, उद्योग के मानकों के अनुसार यह अंतर्निहित मूल्य का करीब तीन गुना या 16 लाख करोड़ रुपये होगा। एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी या 632.49 करोड़ से अधिक शेयर हैं। इन शेयरों का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एक बार सूचीबद्ध होने के बाद एलआईसी का बाजार मूल्यांकन रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) जैसी शीर्ष कंपनियों के आसपास होगा।

क्रेडिट कार्ड खर्च करने से कतरा रहे लोग! जनवरी के आंकड़ों में बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

साल के पहले महीना जनवरी में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने में कमी आई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक मासिक आधार पर जनवरी में क्रेडिट कार्ड से खर्च 6 फीसदी गिरकर 87.7 ट्रिलियन रुपए हो गया। पिछले साल दिसंबर में क्रेडिट कार्ड खर्च 93.9 ट्रिलियन रुपए था। दिसंबर महीने में साल-दर-साल आधार पर भी क्रेडिट कार्ड खर्च में गिरावट दर्ज की गई थी। दिसंबर 2020 में क्रेडिट कार्ड खर्च 47 फीसदी के मुकाबले दिसंबर 2021 में 35 फीसदी रह गया। हालांकि, सालाना आधार पर जनवरी 2022 में खर्च बढ़कर 64.7 ट्रिलियन रुपए पहुंच गया है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने कहा, 'क्रेडिट कार्ड खर्च पूर्व-महामारी के दिनों की तुलना में अधिक है। जनवरी के आंकड़े मासिक गिरावट को दर्शाते हैं, जो ओमिक्रॉन के कारण हुआ। उपभोक्ताओं का भरोसा वापस पटरी पर है, और फरवरी के आंकड़ों में सुधार की उम्मीद है।' एक्सिस बैंक के कार्ड से ज्यादा खर्चः आपको बता दें कि बैंकों में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स ने जनवरी में क्रेडिट कार्ड खर्च में गिरावट देखी। एचडीएफसी बैंक ने 8 फीसदी, घ्घ्घ्घ बैंक ने 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की। वहीं, एँ्घ कार्ड्स ने 2 फीसदी की वृद्धि देखी। इसके अलावा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। इस वजह से बैंक के कार्ड से खर्च में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।